नईदुनिया

# अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाले 16 ईरानी सैन्य जलयानों को नष्ट किया

वाशिंगटन

अमेरिका-इजराइल के ईरान पर 28 फरवरी के सैन्य आक्रमण के बाद अब होर्मुज स्ट्रेट युद्ध के मैदान में बदलता दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी नौसेना ने मंगलवार को होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाले 16 ईरानी जलयानों को नष्ट कर दिया है। दुनियाभर के लिए तेल निकासी की दृष्टि से होर्मुज स्ट्रेट सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने मंगलवार को ईरान की माइन बिछाने वाली 16 नावों को नष्ट कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने विस्तृत जानकारी दी है। कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बारूदी सुरंग बिछाने वाली कम से कम 16 नावों को तहस-नहस कर दिया। अमेरिका का सेंट्रल कमांड मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अमेरिकी सैन्य अभियान की देखरेख कर रहा है। सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अमेरिकी सेना ने 10 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास 16 माइन बिछाने वाली नावों सहित कई ईरानी नेवी के जहाजों को नष्ट कर दिया। पेंटागन और सेंट्रल कमांड के इस दावे के कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पोस्ट में यह संख्या 10 बताई थी। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरंग बिछाने की तैयारी कर रहा है। क्या होते हैं सैन्य जलयान इनके माध्यम से समुद्री क्षेत्र में बारूदी सुरंग बिछाई जाती हैं। इनको माइन बिछाने वाली नाव या बोट भी कहा जाता है। इनका उपयोग दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के रास्ते में विस्फोटक सुरंगें बिछाकर समुद्री रास्तों को असुरक्षित बनाने या किसी विशेष क्षेत्र (जैसे बंदरगाह या जलडमरूमध्य) की रक्षा करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग रणनीतिक जलमार्गों में विशेष रूप से दुश्मन के जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए किया जाता है। यह छोटे आकार की तेज रफ्तार नावों से लेकर बड़े विशेषीकृत जहाजों तक हो सकते हैं। अमेरिका को आशंका है कि ईरानी नौसेना इन नावों का उपयोग समुद्री माइन बिछाने के लिए कर रही है। यह नावें वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा मानी जाती हैं। आधुनिक समय में ऐसी माइन को स्वचालित नावों या रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से भी बिछाया जा सकता है।

## न्यूज ब्रीफ

### ईरान ने रातभर इजराइल पर मिसाइलें दागीं, आईडीएफ का बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला

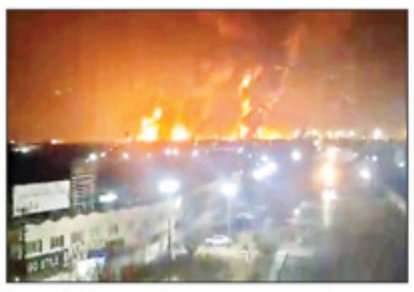

तेल अवीव/तेहरान। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान के 12वें दिन अकेले सामना कर रहे ईरान ने बड़ी चुनौती पेश की है। ईरान ने रातभर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने माना है कि ईरान ने रातभर में तीन बार मिसाइलों से हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स (आईआरजीसी ने कहा है कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दूसरी ओर इजराइल ने रात को लेबनान की राजधानी बेरूत मेंआतंकी समूह हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ के अधिकारियों ने आज तड़के कहा कि ईरान ने आधीरात के बाद सुबह लगभग साढ़े चार बजे के बीच तीन बार मिसाइलों की बौछार की। अधिकतर मिसाइलों को रोक कर नष्ट कर दिया गया। फिलहाल किसी के भी घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें लंबी दूरी की खोरमशहर बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। ईरान का कहना है कि इन मिसाइलों से इजराइल के कई ठिकानों और इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने कहा है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह हार नहीं मान लेता। आईडीएफ का कहना है कि ईरान से हो रही मिसाइलों की बौछार से प्रभावित क्षेत्रों में खतरे के सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है।

### अमेरिका बोला- ईरान के मिसाइल उत्पादन ढांचे को करेंगे तबाह, तेहरान का हाइफा की रिफाइनरी पर हमले का दावा

वाशिंगटन/तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ईरान के मिसाइल उत्पादन से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि पिछले 10 दिनों में चलाया गया अमेरिकी सैन्य अभियान काफी सफल रहा है और सैनिक उम्मीद से भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान की नौसेना के 50 से अधिक जहाजों को नष्ट कर दिया है, जिनमें एक बड़ा ड्रोन कैरियर जहाज भी शामिल है। लेविट ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैन्य अभियान आपरेशन एपिक एयूरी के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य ईरान की मिसाइल तथा सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विश्वास है कि अभियान के लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिए जाएंगे। दूसरी ओर, ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। ईरान के खातम अल-अंबिया सशस्त्र बल मुख्यालय के प्रवक्ता के अनुसार ड्रोन हमलों के जरिए हाइफामें स्थित तेल रिफाइनरी और ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

### माता-पिता के नाम पर...

उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट ने यह साबित कर दिया है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सागर की शैक्षणिक परंपरा गौरवशाली रही है। उन्होंने हरीसिंह गौर के योगदान को याद करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने यहां रानी अवंती बाई लोधी यूनिवर्सिटी की स्थापना कर शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। अब सागर उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मौजूद हैं।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान सागर की बेटी आयुषी अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने जापान के हिमेजी में आयोजित एशिया-अफ्रीका पैसिफिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 425 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आकाश सिंह राजपूत द्वारा आयोजित छह माह लंबी क्रिकेट प्रतियोगिता में दस हजार खिलाड़ियों की भागीदारी को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की पारंपरिक संस्कृति और खान-पान की भी प्रशंसा की। उन्होंने ज्वार, बाजरा और मक्का से बने पारंपरिक व्यंजनों को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में बुंदेली कलाकारों ने राई, बधाई और अन्य लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मुख्यमंत्री ने ज्ञानवीर विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए विधि के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई मूक कोर्ट का अवलोकन किया। किताबों के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में बेहतर अधिवक्ता और न्यायविद बन सकें।

# दो में से एक सैटेलाइट्स का संपर्क टूटा, ईएसए का मिशन संकट में

वाशिंगटन

सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) के दो सैटेलाइट्स में से एक का संपर्क अचानक टूट गया है। स्पेस एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन के सोलर पैनल सूरज की ओर नहीं रहे और बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगी। सैटेलाइट ने स्वयं को सर्वाइवल मोड में डाल लिया और अब यह पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल का कोई जवाब नहीं दे रहा। दिसंबर 2024 में भारत के पीएसएलवी राकेट के जरिए लान्च किए गए इस मिशन की सफलता अब गंभीर खतरे में दिख रही है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इस तकनीकी खराबी की असली वजह का पता नहीं लगाया है। प्रोबा-3 मिशन में दो यान शामिल हैं - कोरोनोग्राफ और आकुल्टर। इनका काम अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्य ग्रहण उत्पन्न कर सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना की तस्वीरें लेना है। दोनों सैटेलाइट्स को एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर उड़ना होता है और उनकी एलाइनमेंट मिलीमीटर स्तर तक सटीक रखी जाती है। आकुल्टर सूरज की तेज रोशनी को ढकता है, जिससे कोरोनोग्राफ कोरोना की इमेजिंग कर पाता है। जून 2025 में मिशन ने पहली बार सूर्य के कोरोना की ऐतिहासिक तस्वीरें भेजकर वैज्ञानिकों और दुनिया को चौंका दिया था। 6 मार्च 2026 को ईएसए ने जानकारी दी कि कोरोनोग्राफ यान में तकनीकी खराबी के कारण एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। यान ने अपनी दिशा खो दी, सोलर पैनल सूरज की ओर नहीं रहे और बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगी। इसके बाद यान सर्वाइवल मोड में चला गया और अब अंतरिक्ष में केवल एक धातु का टुकड़ा तैरता नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मिशन की सफलता अत्यधिक सटीकता पर निर्भर है। अब ईएसए की टीम सुरक्षित बचे आकुल्टर यान को खराब हुए कोरोनोग्राफ के पास ले जाकर स्थिति का आकलन करने पर विचार कर रही है। यह कदम जोखिम भरा है, लेकिन इससे यह पता लगाया जा सकता है कि यान में कितनी क्षति हुई है और क्या इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। यदि अगले कुछ दिनों में संपर्क नहीं सुधरा, तो करोड़ों यूरो के इस मिशन की पूरी सफलता खतरे में पड़ सकती है। प्रोबा-3 का मिशन इस लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य का कोरोना वह हिस्सा है, जहां से सौर तूफान उत्पन्न होते हैं।

### ईरान युद्धः भारत से तेल सप्लाई बंद हुई तो पुतिन के सामने गिड़गिड़ाएगा यूरोप अभी से कांप उठा हंगरी

बुडापेस्ट। दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर एक तरफ युद्ध की लपटें तेज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ यूरोपीय अर्थव्यवस्था की धड़कनें ठंडी पड़ती दिखाई दे रही हैं। इस बीच हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो के एक हालिया बयान ने पूरे यूरोप की बेचैनी को सतह पर ला दिया है। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में एक संकटमोचक की रही है। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए भारत ने साबित किया कि उसका मध्य मार्ग सबसे सटीक था। हालांकि, यदि समुद्री बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, तो भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि ऊर्जा सुरक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र केवल अपनी राजनीतिक विचारधारा के दम पर आगे नहीं बढ़ सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून के संदर्भ में देखें तो रूस पर लगे प्रतिबंध पश्चिमी देशों के अपने निजी फैसले हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक समर्थन प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि भारत और चीन जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप अपनी ईगो को किनारे रखकर ऊर्जा वास्तविकता को स्वीकार करेगा पिछले दो वर्षों से यूरोपीय देश जिस रूसी तेल का उपयोग भारत की रिफाइनरियों के रास्ते कर रहे थे, अब उस पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते बारूदी संघर्ष ने ब्रुसेल्स के रणनीतिकारों को हिलाकर रख दिया है। डर इस बात का है कि यदि भारत से होने वाली तेल की आपूर्ति बाधित हुई, तो यूरोप का ऊर्जा सूरज हमेशा के लिए अस्त हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने नैतिकता का हवाला देकर रूसी कच्चे तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए उसने एक पिछले दरवाजे का सहारा लिया। भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा, उसे अपनी उन्नत रिफाइनरियों में संसाधित किया और फिर डीजल व जेट फ्यूल के रूप में यूरोप को निर्यात किया। तकनीकी रूप से यूरोप जिन विमानों और गाड़ियों को दौड़ा रहा था, उनका मूल स्रोत रूस ही था।

# तीसरे विश्व युद्ध में हो सकता है 12 हजार न्यूक्लियर मिसाइलों का उपयोग

वाशिंगटन

तीसरे विश्व युद्ध के दौरान यदि दुनिया भर की करीब 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलों का उपयोग होता है, तो अनुमानित 5 अरब लोग मारे जाएंगे और पूरी पृथ्वी न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीत की चपेट में आ जाएगी। इस स्थिति में दस साल तक दुनिया के बड़े हिस्सों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड बनी रहेगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों और हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, इस भीषण परिदृश्य में केवल दो देश - आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड - ही जीवित रहने में सक्षम हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन देशों की भौगोलिक स्थिति उन्हें परमाणु शीत की मार के बावजूद कृषि और जीवन बनाए रखने में मदद करेगी। एनी जैकबसन, जो न्यूक्लियर वार: ए सिनेरियो की लेखिका और आर्मगेडन विशेषज्ञ हैं, ने चेतावनी दी कि परमाणु विस्फोटों से निकलने वाली आग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती धमाकों में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन असली तबाही उसके बाद शुरू होगी। कृषि प्रधान क्षेत्रों जैसे आयोवा और यूक्रेन में दस साल तक बर्फ और ठंड की वजह से खेती पूरी तरह विफल हो जाएगी, जिससे लोग भूख और हालात की मार से मरेंगे। जैकबसन ने कहा कि ओजोन परत को नुकसान और रेडिएशन की मौजूदगी स्थिति को और भयावह बना देगी। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोग जीवित तो रहेंगे, लेकिन उन्हें अंधेरे में रहना होगा, भोजन के लिए संघर्ष करना होगा और रेडिएशन से बचने के लिए भूमिगत आश्रय लेना होगा। हालांकि इन देशों की समुद्र से दूरी और भौगोलिक स्थिति उन्हें तापमान में कटौती और कुछ हद तक सुरक्षित रहने में मदद करेगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, और दोनों पक्षों से हमले और पलटवार हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से युद्ध जारी है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान ने परमाणु संपन्न पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की धमकी दी है।

### राष्ट्रपति ट्रंप का अनुमान फेल, अमेरिका पर उम्मीद से ज्यादा भारी पड़ रहा ईरान

वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा सैन्य संघर्ष अब अमेरिकी सेना के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। पेंटागन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, ईरान के हमले में घायल एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है, जिससे इस युद्ध में अब तक मारे गए अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि यह सैनिक 1 मार्च को सऊदी अरब स्थित एक सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे बेहतर इलाज के लिए जर्मनी भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन शनिवार रात उसने दम तोड़ दिया। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुमान से कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है ईरान। यह क्षति ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में डोवर एयर फोर्स बेस पर उन छह सैनिकों के पार्थिव शरीरों की अगवानी की थी, जो कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर हुए ड्रोन हमले में मारे गए थे।

# संत थिरुमंगई अलवर की 16वीं सदी की दुर्लभ कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाएगा ब्रिटेन

### यह मूर्ति करीब 500 साल पहले तमिलनाडु के साउंडरराजा पेरुमल मंदिर से ले जाई गई थी

ब्रिटेन

ब्रिटेन ने दक्षिण भारत के वैष्णव संत थिरुमंगई अलवर की 16वीं सदी की दुर्लभ कांस्य प्रतिमा भारत लौटाने का फैसला किया है। यह मूर्ति करीब 500 साल पहले तमिलनाडु के साउंडरराजा पेरुमल मंदिर से ले जाई गई थी और 1967 में नीलामी के जरिए म्यूजियम तक पहुंची थी। रिसर्च और जांच के बाद अब इसे अपने मूल स्थान पर लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संत थिरुमंगई अलवर दक्षिण भारत के 12 वैष्णव अलवर संतों में अंतिम और बेहद प्रसिद्ध माने जाते हैं। वे 8वीं सदी के महान भक्त और कवि थे, जिनका असली नाम कलियान था और पहले वे सैन्य कमांडर थे। आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया और दिव्य प्रबंधम नामक तमिल भक्ति साहित्य में छह अहम रचनाएं लिखीं, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित 4000 भक्ति स्तोत्र शामिल हैं। उन्होंने श्रीरंगम मंदिर के निर्माण और विस्तार में भी योगदान दिया। कांस्य से बनी यह

प्रतिमा करीब 57-60 सेंटीमीटर ऊंची है। म्यूजियम ने यह मूर्ति 1967 में प्रसिद्ध नीलामी संस्था सूथेबी से खरीदी थी। उस समय इसे खरीदा गया, लेकिन प्रतिमा के पहले के इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी।

रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में फ्रांसीसी रिसर्चर ने पुडुचेरी के अभिलेखागार में 1957 में मंदिर में खींची गई मूर्ति की तस्वीर देखी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मूर्ति चोरी हुई थी। इसके बाद म्यूजियम ने इसकी उत्पत्ति की जांच शुरू की और भारत के उच्चायोग से संपर्क किया। 11 फरवरी 2020 को मंदिर के अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि मंदिर में रखी मूल कांस्य प्रतिमा की जगह आधुनिक प्रतिकृति रख दी गई थी। इसके बाद 3 मार्च 2020 को भारतीय उच्चायोग ने म्यूजियम में औपचारिक दावा पेश किया। ऐशमोलियन म्यूजियम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुरोध पर मूर्ति की धातु संरचना की जांच भी करवाई। म्यूजियम के निदेशक ने कहा कि हमें खुशी है कि यह कलाकृति भारत लौट रही है। हम भारतीय अधिकारियों और विद्वानों के आभारी हैं जिन्होंने इसके इतिहास को स्थापित करने में मदद की।

रिपोर्ट के मुताबिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता और इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट ने बताया कि मूर्ति तमिलनाडु के साउंडरराजा पेरुमल मंदिर से जुड़ी है और 1957 की तस्वीरों के जरिए इसकी पहचान हुई। भारत लौटाने की पूरी प्रक्रिया में करीब आठ साल लगे।

# नेपाल में वामपंथी दल दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए

काठमांडू

पांच मार्च को हुए संसदीय चुनाव में जहां राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है और यह दल दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, वहीं लंबे समय से सत्ता पर कब्जा जमाए हुए वामपंथी दलों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया है।

प्रत्यक्ष मत परिणाम आने के बाद नेपाल के प्रमुख वामपंथी दल को 10 सीट भी नहीं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्कमल दहाल प्रचण्ड के नेतृत्व वाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 7 सीट ही मिल पाई। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डा बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व वाले प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसी तरह माओवादी सहित अन्य छोटे वामपंथी दलों का भी सूपड़ा साफ हो गया है। भारत के विरोध में राष्ट्रवाद की राजनीति कर सत्ता तक पहुंचने वाले वामपंथी दलों को इस बार जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल में 1990 के जन आंदोलन के बाद से दशकों तक राजनीति पर प्रभाव बनाए रखने वाले कम्युनिस्ट दल अब अभूतपूर्व अस्तित्व संकट का सामना कर रहे हैं। विश्लेषकों और हालिया चुनाव परिणामों के अनुसार, कम्युनिस्ट दलों का प्रभाव तेजी से घट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मुख्य कारण नेतृत्व के भीतर लगातार विवाद और अस्थिर नीतियां हैं, जिससे आने वाले वर्षों में कम्युनिस्ट प्रभाव और कम होने की आशंका जताई जा रही है। ऐतिहासिक रूप से नेपाल में कम्युनिस्ट दलों की स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रही है। वर्ष 1959 के पहले आम चुनाव में 109 सीटों में से कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल को केवल चार सीटें मिली थीं, जबकि नेपाली कांग्रेस ने 74 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। पंचायत व्यवस्था समाप्त होने के बाद कम्युनिस्ट गुट धीरे-धीरे नेपाली कांग्रेस के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के

रूप में उभरने लगे। 1991 के चुनाव में 205 सीटों में से सीपीएन-यूएमएल ने 69 सीटें जीतीं, यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने 9 सीटें और नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने 2 सीटें हासिल कीं। 1994 के मध्यावधि चुनाव में यूएमएल ने 88 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफलता पाई, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को चार सीटें मिलीं। 1990 के संविधान के तहत हुए अंतिम चुनाव (1999) में यूएमएल ने 71 सीटें जीतीं, राष्ट्रीय जनमोर्चा को 5, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को 1 और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट को 1 सीट मिली। एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह और 2006 के 19-दिवसीय जनआंदोलन के बाद 2008 में हुई संविधान सभा चुनाव कम्युनिस्ट दलों के लिए चरम सफलता का दौर साबित हुए। उस समय सीपीएन (माओवादी) ने 601 में से 220 सीटें जीतीं, यूएमएल को 103, सीपीएन (एमएल) को 8, जनमोर्चा नेपाल को 5, सीपीएन यूनाइटेड को 5, राष्ट्रीय जनमोर्चा को 3 और वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को 2 सीटें मिलीं। इस तरह संविधान सभा में कम्युनिस्ट दलों का व्यापक प्रभाव स्थापित हो गया था। हालांकि बाद के वर्षों में कम्युनिस्ट गुटों के बीच विभाजन और आंतरिक संघर्ष के कारण उनकी चुनावी ताकत कमजोर होती चली गई। 2013 के संविधान सभा चुनाव में माओवादी पार्टी की सीटें घटकर 80 रह गईं, जबकि यूएमएल 175 सीटों तक पहुंच गई। वहीं सीपीएन (एमएल) को 5, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को 4, राष्ट्रीय जनमोर्चा को 3 और सीपीएन यूनाइटेड को 3 सीटें मिलीं। इसके बावजूद कम्युनिस्ट दलों का समग्र प्रभुत्व पहले की तुलना में कमजोर हो गया। 2017 में प्रमुख कम्युनिस्ट दलों के लेफ्ट एलायंस में एकजुट होने से उन्हें फिर से संसदीय बहुमत मिला, जो 2022 के चुनाव तक जारी रहा। लेकिन फाल्गुन 21 को हुए ताजा चुनावों में छोटे कम्युनिस्ट दल लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए हैं और केवल यूएमएल तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सीमित उपस्थिति ही बची है। शहरी मतदाताओं के मतदान पैटर्न से स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्होंने कम्युनिस्ट दलों को नकार दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति 1950 के शुरुआती दशक में उनके कमजोर प्रभाव जैसी हो सकती है। यदि दलों ने गंभीर सुधार नहीं किए, तो नेपाली राजनीति में उनकी भूमिका और सीमित हो सकती है।